International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(II), July - September, 2024, pp. 33-40

मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उघोगों के विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियांः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. धीरज शर्मा*
लखन लाल चौकसे**

सार

मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में लघु उघम क्षेत्र का अतुलनीय योगदान रहा हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 50 प्रतिशत औघोगिक इकाइयां आती है। लघु उघम क्षेत्र द्वारा लगभग 5000 से भी अधिक पारंपरिक एवं हाईटेक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन इकाइयों द्वारा राज्य के 40 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। उघमशीलता को बढावा देने, रोजगार प्रदान करने, एवं नवप्रवर्तनशीलता को प्रोत्साहित करने में यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में लघु उघम का महत्व स्वीकारते हुए इसके विकास हेतु उन्हें प्रेरित करने हेतु अनेक नीतिगत कदम उठाये गए हैं। इसमें प्रमुख रुप से प्रौघेगिकी उन्नयन हेतु योजनाएँ, गुणवत्ता मे सुधार हेतु नीतियां ऋण पाने हेतु अनेक योजनाए एवं उत्पादों को बाजार में विक्रय हेतू नीतियां शामिल है। भारत की केन्द्र तथा राज्य सरकारें लघु उघम के विकास हेतु विभिन्न संस्थागत एवं नीतिगत प्रयास करती है। ये नीतियां लघु उघोगों के वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उघोगों की क्या संभवनाएं है एवं इसके सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। उघमियों की व्यापार संचालन में आने वाली समस्याओं और समाधान को प्रस्तुत शोधपत्र में दर्शाया गया है एवं निष्कर्ष निकाले गए है।

शब्दकोशः *लघु उघोग, आर्थिक विकास, श्रमशक्ति एवं रोजगार।*

प्रस्तावना

आर्थिक विकास में उघोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उघोगों में विशेषकर लघु उघोगों का विशिष्ट स्थान होता है क्योंकि यह काम पूँजी, कम साधन एवं बिना प्रशिक्षण के परम्परागत रुप से संचालित किये जाते है। यघपि लघु उघोगों में अनेक समस्याएं भी है जैसे पूँजी की कमी, कच्ची सामग्री की समस्या, उत्पादन की धीमी गति, बाजार का अभाव, सरकारी उदासीनता एवं नवाचार का अभाव आदि। लघु उघोगों के विकास के लिए उत्पादित वस्तुओं को नवीन डिजाइनों में तैयार करना चाहिए। इन उघोगों का पर्याप्त वित एवं मशीनों को उपलब्ध कराना चाहिए आवश्यमतानुसार प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता, उघमियों को विभिन्न वित्तों, माध्यमों, तकनीको आदि जानकारी के समुचित प्रचार – प्रसार होना, अनुदान के लिए सरल एवं स्पष्ट नियम होना चाहिए ताकि उघमियों को अनुदान प्राप्त हो सकें। लघु उघोगों की वस्तुऐ घरेलू उपयोग के साथ – साथ विदेशों को भी नियार्त की जाती है अतः इन उघोगों का महत्व औघोगीकर, रोजगार निर्माण, निर्यातोन्मुखी वस्तुओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

* सहायक प्राध्यापक एवं शोधनिर्देशक, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविघालय, खातेगॉव, मध्यप्रदेश।
** शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविघालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

साहित्य पुनरावलोकन

साहित्य पुनरावलोकन में शोध पत्रों पुस्तकों एवं रिपोर्टों का अध्ययन किया गया हैं।

शर्मा अशोक (2011) इस शोध अध्ययन में पाया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघोग के विकास में कार्यरत पूँजी की उपलब्धता एवं उचित प्रबन्धन सहायक सिद्ध होगा, जो नियति एवं रोजगार सृजन में कारगर सिद्ध होता है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम को आर्थिक एवं नीतिगत सरकारी योजना बनाकर समस्याए कम एवं तीव्र गति से विकास होगा।

गार्ग सोनू एण्ड अग्रवाल पारुल (2017) "माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया : " रीव्यू ऑफ ग्रोथ एण्ड चेलैन्जेस इन दा प्रनेट सेनेरिओं "में वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघमों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव दिये गये है। इन्होने अपने शोध अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि आर्थिक समस्याओं को हल करने और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए औघोगीकरण एक प्रभावी उपाय है।

एम. एस. कुमारी लवपा आर. (2017) प्रस्तुत शोधपत्र "इम्पेक्ट ऑफ गुडस एण्ड सर्विस टैक्स ऑन इण्डिया एमएसएमई" में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघोगों के जीएसटी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघोग भारतीस अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालाक है। यह विनिर्माण जीडीपी का लगभग 7 प्रतिशत और सेवाओं का जीडीपी में 31 प्रतिशत योगदान देता है। इस शोधपत्र के प्रमुख उद्देश्य माल और सेवा कर की अवधारणा का समझना,सूक्ष्म एवं मध्यम उघोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघमों के लिए अवसरों की जांच करना।

वैंकटेश एवं मुथैया (2012) ने अपने शोधपत्र में पाया है कि लघु उघोग रोजगार के साथ – साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देते है। लघु उघोग सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगा।

साहित्य पुनरावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उघोगों के विकास की संभावनाएँ है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पडता है ।

उद्देश्य

इस शोधपत्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उघोगों के विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उघोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उघोगों के विकास के लिए कारकों की पहचान करना।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उघोगों के विकास के लिए सुझाव देना कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और संभावनाओं को बढावा दिया जा सकता है।

परिकल्पना

प्रमुख परिकल्ना निम्नतिखित है।

- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उघोगों के विकास की संभावनाएं सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उघोगों के सामने आने वाली चुनौतियों बाजार की मांग एवं प्रतिस्पर्धा से संबंधित है।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उघोगों के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता है।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उघोगों के विकास के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राप्त समंकों का वर्गीकरण कर सारणीयण एवं विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।

- **प्राथमिक समंक** – प्राथमिक समंक विभिन्न उघमियों के साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार व संख्याओं द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।
- **द्वितीयक समंक** – द्वितीयक समंक लघु एवं उघोगों से संबंधित शोध – पत्रिकाएँ सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशनों, प्रतिवेदनों, गजट, अधिसूचनाओं, जनरल एवं संचार माध्यम से प्राप्त किये गये है।

विषय विश्लेषण

- **लघु उघोगों की संभावनाएं** –लघु उघोग कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखते है एवं ग्रामीण औघोगीकरण को प्रोत्साहित करते है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लघु उघोगों के समक्ष चुनौतियां एवं अवसर दोनों ही आये है। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार, उघमियों तथा लघु उघोग संगठनों को आपस में तालमेल से काम करना होगा, क्योंकि गेम थ्योरी जैसे सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वर्तमान में लघु उघोगों को अनेक सुविधायें मिल रही है फिर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु उघोग नवीनतम तकनीक का उपयोग करे तथा गला काट प्रतिस्पर्धा से बचते हुए उच्च स्तर का उत्पादन करे। सरकारी अनारक्षण नीति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के फलस्वरुप लघु उघमों के सामने प्रतिस्पर्धा की समस्या उत्पन्न हो गई है फिर भी लघु उघोगों के भविष्य का विवेचन निम्न तर्कों के आधार पर किया जा सकता है –
  - **कृषि के लिए पूरक व्यवसाय** – मध्य प्रदेश का समग्र विकास केवल कृषि से संभव नहीं है कृषि विकास का लाभ प्रत्यक्ष रुप से खेतिहर मजदूर या भूमिहर श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। यदि अप्रत्यक्ष रुप से लाभ मिल भी जाता है तो वह नगण्य है। अतः ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है। कि लघु उघमों और सहायक व्यवसाय का विकास किया जाये ताकि कृषि कार्य की बदली हुई परिस्थिति और लोगों की रुचि में सामंजस्य से निरन्तर विकास कार्य को गतिमान रखा जा सके। औघोगीकरण से गैर कृषि साधनों की मांग में वृद्धि हुई है इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि गैर कृषि कार्यों में लग सकने वाले व्यक्तियों या रोजगार अवसरों की सम्भावना भी असीमित है।
  - **उत्पादन का उपयुक्त क्षेत्र –** ग्रामीण आवश्यकतायें अत्यंत वृहत एवं विशाल है। जब इन्हें पूरा करने की चेष्टा की जाती है तो ग्रामीणों में एक नई जाग्रति आने की सम्भावना हो जाती है। अतः लोगों की इसमें भागीदारी स्वभाविक है जहां तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को बाह्य रुप से लागू करने का प्रश्न है ग्रामीण इसे राजनीति से प्रेरित मान सकते है। इस प्रक्रिया में ग्रामीणों का ध्यान अनावश्यक तथ्यों की और आकर्षित होता है। जबकि ग्रामीण विकास का मौलिक तथ्य अछूता रह जाता है।
  - **अपेक्षाकृत अधिक रोजगारपरक उघम –** पूर्ण रोजगार की व्यवस्था एक स्वप्न लगने लगा है। बेरोजगारी के ऑकडे उपलब्ध करने में योजना असफल रहा है तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता बहुत स्पष्ट नहीं है। नियोजन प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अवसरों को सृजित करने के सभी प्रयास श्रम बाजार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने में असफल रहे है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाये गये सरकारी कदम प्रभावी साबित नहीं हो सका है अतः लघु उघोग ही इन अतिरिक्त श्रमिको को नियोजित करने की क्षमता रखता है।

- **महिला श्रमिकों के लिये विशेष उपयोगी** – प्रौघोगिकी का पक्ष प्रस्तुत करते समय विभिन्न पैशों मे लिंग सहभागिता अनुपात को ध्यान में रखना चाहिये। उदाहरण के लिये विभिन्न प्रक्रिया जैसे भवन निर्माण, सडक निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुरुष श्रमिकों का अनुपात अधिक है। यदि प्रौघोगिकी के प्रयोग के कारण महिलाओं की सहभागिता अनुपात में कमी आती हो तो इससे सामाजिक समस्यायें घटने की बजाय बढेगी इसलिये मशीनों के प्रयोग से महिला रोजगार विपरीत दिशा में प्रभावित न हो इसका ध्यान रखना होगा। अतः स्पष्ट है कि तकनीक का चुनाव केवल श्रम बनाम पूजीं के आधार पर नही होना चाहिये बल्कि महिला श्रमिकों के प्रतिस्थापन प्रभाव को ध्यान में रख कर, इन लघु उघोगों में विशेष रुप से महिला श्रमिकों की सहभागिता को और अधिक बढाया जा सकता है।

भविष्य में राज्य का और अधिक विकास करके उघोगों को रोजगार में अंश बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन कार्य व लघु उघोगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उघोगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज सम्पदा विपुल माना गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं विघमान है। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विघुत गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औघोगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढेगी तथा उसके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। गलीचों, चमडे की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तओं तथा रत्न आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औघोगिक रोजगार का विस्तार किया जाना आवश्यक है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम कह सकते है कि लघु उघोगों का भविष्य अति उज्जवल है। वर्तमान में लघु उघोग बदली हुई परिस्थितियों के अनुरुप नवीन प्रौघोगिकी को अपनाकर एवं उत्पाद लागत को क्रम करके ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा विकासशील देशों के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षमक कर सकेगा।

लघु उघोग में व्याप्त चुनौतियां

लघु उघोग में व्याप्त चुनौतियां निम्नलिखिए है।

- **कच्चे माल की समस्या** – अधिकांश लघु उघोग कच्चे माल हेतु स्थानीय स्त्रोतों पर निर्भर रहते है। लेकिन स्थानीय स्त्रोत दोहरा शोषण करते है, जैसे कच्चे माल की ऊंचे दाम पर बेंचना व निर्मित माल कम कीमत पर खरीदना। लघु उघोग जिन वस्तुओं का उत्पादन करते है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः बडे. उघोग करते है, फलस्वरुप लघु उघमी कच्चे माल से वंचित रह जाते हैं, जबकि बडे उघमी कच्चे माल को थोक में खरीद लेते है।
- **वित की समस्या** – लघु उघोगों की सर्वाधिक वित्तीय समस्या है, क्योंकि ऐसे उघमों को वित प्राप्त करने में विशेष कागजी कार्यवाही करनी पडती है, जो लघु उघमियों के लिए कठिन है इसके अलावा वित्त प्राप्त करने मे समय की बर्बादी होती है जिससे लघु उघमी निराश होकर बैंक, वित्त निगम व भारतीय लघु उघोग विकास बैंक आदि का सहारा छोडकर स्थानीय महाजन अथवा साहूकार से ऋण प्राप्त कर लेता है।
- **बडे उघोगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या** – भारत में बडे उघोग की तरह लघु उघोग भी स्वतन्त्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन क्रियायें करते है। इससे दोनों प्रकार के उघोगों में न केवल बाजरी–प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, बल्कि कच्चे माल, वित्त सुविधा प्राप्त करने में भी कलागाट प्रतिस्पर्धा होती है। इसी का परिणाम है कि लघु उघोग हो जाते है।

विपणन की समस्या

- चूकिं ऐसे उघमियों की बाजार में कोई दुकाने नहीं होती है, जहॉ उत्पादित माल सरलता से बेंचा जा सकें। फलत : फुटपाथ पर वस्तुएॅ रखकर विपणन करना पडता है।
- ऐसे उत्पादकों को अपनील वस्तुएॅ बिचौलिये के हाथों बेंचनी पडती है, जिससे उन्हें वस्तु की उचित कीमत नहीं मिल पाती है।
- ऐसे उत्पादकों की वस्तुएं प्रमाणीकरण व वर्गीकृत नहीं होती है, अतः प्रत्येक वस्तु का अलग – अलग मूल्य होता है।
- ऐसे उत्पादकों के उपभोक्ताओं की रुचि का ज्ञान नहीं होता है, अतः रुचि के विपरीत वस्तुएॅ बेचनी पडती है।

प्रमाणीकरण की समस्या

भारतीय लघु उघोगों का उत्पादन सदैव अप्रमाणित रहता है, जिससे उन्नत किस्म समरुप व वगीकृत वस्तुओं का अभाव है। इससे उघम के श्रमिक, कारीगर व मालिक उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाते है।

अकुशल कारीगरों की समस्या

कुटीर एवं लघु उघोगों में अकुशल श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लघु उघमी न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को उघोग मे रखते है, इसका कुप्रभाव उत्पादन पर पडता हैं। अत : असल मजदूरी न मिलने के कारण भी कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं होते है।

करभार की समस्या

सरकारी आदेशों में लघु उघोगों कर मुक्त हैं। वास्तव में लघु उघोग कर मुक्त है, परन्तु लघु उघोग अनेकानेक करों का भुगतान करना पडता है। अतः कुटीर एवं लघु उघोंगों का कर भार ऐसा है जिसे उपभोक्ताओं पर भी विवर्तित नहीं किया जा सकता है।

कुशल प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव

यदि कुटीर है, जिनमें लघु स्तरीय उत्पादन करने के लिए 75 लाख रु. तक की पूॅजी विनियोजित करके 11 मजदूर से 50 मजदूर तक किराये पर रखकर कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

लघु उघोगों की समस्यामुक्त करने के उपाय

लघु उघोग में समस्यामुक्त करने के उपाय निम्नलिखिए है।

- **वित्त की व्यवस्था** – लघु उघोगों की वित्तीय व्यवस्था हेतु विशिष्ट वित्तीय संस्थाएॅ जैसे– व्यापारिक बैंक व राज्य वित्त निगम आदि स्थापित होने चाहिए। जो सरलता से ऐसे उघोगों को ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार एवं लघु उघोगों के लिए बैंक को ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए, जिससे लघु उघमी भी तरलता अधिमान दे सकें।
- **कच्चे माल की उपलब्धता** – कच्चा माल सुगमता से लघु उघमियों को प्राप्त हो सकें, इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होनी चाहिए, जो सामान्य वस्तुओं से सम्बन्धित इकाइयों के कच्चे माल को उपलब्ध करायें।
- **तकनीकी सहायता** – तकनीकी सहायता से उघम की उत्पादन कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। नवीन वस्तुओं का उत्पादन भी तकनीकी सहायता पर निर्भर है। यह तकनीकी सहायता सरकार को लघु उपकरण, यंत्र, विघुत चालित मशीनों के रुप में कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए।

- **बडे एवं लघु उघोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाए –** सरकार का दायित्व है कि लघु उघोगों से निर्मित वस्तुओं का बाजार सुरक्षित किया जाये, जहॉ बडे पैमाने के उघोंगों से निर्मित वस्तुऍ नहीं विक्रय होनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि बडे उघोग प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसी इकाइयों पर निर्भर हो जायें।
- **करों मे छूट –** चूकि लघु इकाइयों के उत्पादक कर भार को वस्तुओं की कीमत पर विवर्तित नही कर पाते है। इसलिए लघु उघोगों को शैशवावस्था में कर मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन लाभ में चलने वाली इकाइयों पर न्यूनतम कर भी लगाये जा सकते है।
- **विपणन सुविधाऍ –** सरकार को विपणन व्यवस्था हेतु कुछ ऐसे बाजार निर्मित करने चाहिए जहॉ ऐसे उघोगों का माल विक्रय हो। इसके अलावा सरकार केन्द्रीय विपणन संस्थाओं की स्थापना करें, जो ऐसे उघमियों से प्रत्यक्ष रुप में माल खरीदें और निर्यात की व्यवस्था करे, यदि सम्भव हो तो ऐसे उघोगों को सस्ते परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- **उघोगों में प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू हो –** सरकार को उन्नत किस्म का आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि प्रमाणीकरण के अन्तर्गत नमूना या ट्रेडमार्क प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ उघोग परिष्कृत हो सकें। यह व्यवस्था प्रारम्भ में दस्तकारी वस्तुओं,खेलकूद के सामान व लघु इंजीनियरिंग से प्रारम्भ होनी चाहिए।
- **निःशुल्क लाइसेंस –** लघु उघोगों को निःशल्क लाइसेंस देना आवश्यक है, क्योंकि लघु उघम स्थापित करते समय उघमियों को सर्वप्रथम लाइसेंस प्राप्त करना पडता है, जिसकी प्रक्रिया सरल नहीं है।
- **अनुसंधान केन्दों की स्थापना एवं प्रशिक्षण –** इन उघोगों को विकास करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित होने चाहिए, जो न्यूनतम लागत पर परिष्कृत उच्च कोटि की वस्तुऍ उत्पादित करने में उघमी का सहयोग करें। इसी प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के अभाव में अकुशल श्रमिक की उन्हें उपलब्ध हो पाते है। अतः सरकार को "ट्रेनिंग सेन्टर्स " स्थापित करने चाहिए, जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करें।
- **प्रदर्शिनियों एवं मेलों का आयोजन –** ऐसे उघोगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए पृथक प्रदशनियाँ एवं मैलों का आयोजन किया जाए।
- **लघु उघोग द्वारा उत्पादित सामग्री –** लेखन सामग्री का उत्पादन, आयुवेदिक फार्मेसी, सौंदर्य व श्रृगार प्रसाधन उघोग, प्रिटिंग इंक उघोग, अगरबत्ती उघोग, आइस – क्रीम उघोग, डेरी उघोग, कन्फैक्शनरी उघोग, मोमबत्ती उघोग, वांशिग डिटरजेंट पाउडर, पापड, बडियां और चाट मसाला उघोग, लैटेक्स रबड उघोग, रबड की हवाई चप्प्ल बनाना, कटाई बिनाई आदि विभिन्न कार्य लघु उघोग के स्तर पर हो रहे है। दरजी, बढई, लोहार आदि के परंपरागत पेशे इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग छोटे स्तर पर धातुकर्म, चमडे का काम, विभिन्न मशीनों के पुर्जे बनाने का काम, ईट बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम आदि कर रहे हैं जो आधुनिक लघु उघोगों के सर्वोत्तम उदाहरण है।

लघु को बढावा देने के लिये योजनायें

लघु को बढावा देने के लिये योजनायें निम्नलिखिए है।

- **उघमी मित्र पोर्टल –** सिडबी द्वारा एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहेल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये लॉन्च किया गया।
- **एमएसएमई संबंध –** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उघमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

- **एमएसएमई समाधान** – एमएसएमई विलंबित भुगताान पोर्टल देश भर के सूक्ष्म और लघु उघोग को केंन्द्रीय मत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिये सशक्त करेगा।
- **डिजिटल एमएसएमई योजना** – इसमें क्लाउड कंम्प्यूटिंग का उपयोग शामिल है जहाँ एमएसएमई इंटरनेट का उपयोग आम और साथ ही दर्ज आईटी बुनियादी ढाँचे तक पहुँचने के लिये करते है।
- **प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** – यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- **पारंपरिक उघोगों के उत्थान के लिए निधि की संसोधित योजना** – पारंपरिक उघोगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना और उनकी विपणन क्षमता को बढाकर और उन्हें बेहतर कौशल से लैस करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **नवाचार, ग्रामीण उघोग और उघमिता को बढावा देने के लिये एक योजना** – नई नौकरियां पैदा करती है और बेरोजगारी को कम करती है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम** – भारतीय एमएसएमई के बीच उनकी प्रक्रियाओं, डिजायन, प्रौघोगिकी और बाजार पहुँच मे सुधार करके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विकसित करना।
- **सूक्ष्म और लघु उघम क्लस्टर विकास कार्यक्रम** – लघु`की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने के साथ–साथ क्षमता निर्माण के लिये क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाता है।

एमएसएमई के लिये प्रौघोगिकी के उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना चालू है। ठसलिए सरकार को मानव क्षमता विकास,ज्ञान सेवाओं वित्त तक पहुँच, प्रौघोगिकी, बुनियादी ढाँचे, बाजार पहुँच और व्यापार करने में आसानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई के समग्र विकास के लिये ठोस प्रयास करना जारी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश राज्य परंपरागत रुप से कृषि प्रधान राज्य है। यह कि लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह की अधिकांश जनसंख्या कृषि के बाद लघु उघोगों को व्यवसाय के रुप में अपनाते है। उन उघम के विकास पर मध्यप्रदेश एवं भारत देश का विकास निर्भर करता है। अब हमे मध्यप्रदेश एवं भारत देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है, तो इन उघमों का विकास करना होगा। इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का उचित समाधान करके ही इनका विकास किया जा सकता है। लघु उघोग राज्य के अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य मार्ग की कुँजी है जिसके द्वारा उसके साधनों का दोहन तथा लाखों व्यक्तियों के उत्पादन की क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। लघु उघोगों के विकास के माध्यम से वर्तमान रोजगार सृजन कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह क्षेत्र अकुशल श्रमिकों के कौशल को उन्नत कर उन्हें रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार भी इस हेतु प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र की समस्याओं पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना होगा तभी यह क्षेत्र विकसित हो सकेगा। आधुनिक समय मे लघु उघोगों को नवीन प्रौघोगिकी से अवगत कराया जाए, जिससे यह उघम बडे उघमों के समान बाजार मे अपना प्रभुत्व कायम कर सकें। परिणामस्वरुप लघु उघम क्षेत्र स्वयं के विकास के साथ साथ राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2022 – 23 भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2023 – 24 भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विकास संस्थान, इंदौर वार्षिक रिपोर्ट, 2022 – 23।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विकास संस्थान, इंदौर वार्षिक रिपोर्ट, 2023 – .24।

5. बागडी डालचन्द (2008).भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।

6. शर्मा, वैष्णव (2007). विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा।

7. सिन्हा, वी.सी .(2003). अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

8. आनन्दस्वरुप (2002) अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

9. दैनिक. भास्क, इन्दौर।

10. टाइम्स ऑफ इंडिया।

11. उघोग व्यापार, भोपाल. मासिक।

12. mospi.gov.in

13. www.msmeindore.nic.in

14. www.msme.gov.in

15. www.msme.nic.in

16. www.mpindustry.gov.in

17. Garg sonu and Agrawal parul, (2017), “Micro, Small and Medium Enterprises in india: A review of Growth and Challenges in the present scenario”, International journal if applied business and economic research, ISSN: 0972 - 7302, vol - 15, p. p. 569 - 580.

18. Kumara, Lavanya R., (2017), “Impact of goods and service tax (GST) on Indian MSMEs”, International journal of research in economics and social sciences (IJRESS), vol - 7, issue-7, p. p. 334 - 348, ISSN: 2249 - 7382.

19. Kumar Himani maggo, (2017), “Role of enterpreneurial development programmes in growth of entrepreneurship in india”, international journal of latest technology in engineering management & applied science, (IJLTTEMAS), vol - vi, issue - vi, ISSN: 2278 -2540, p.p. 22 - 26.

20. Tripathi sourabh, (2016), “challenges faced by MSME sector in india”, internation journal of science technology and management, vol - no. 5, issue - no 3 ISSN 2394 - 1537.

21. Hiramath s chaitra, (2016), “Overview of Indian MSME - An exploratory approach”, international journal of advance research in computer science and management studies, vol - 4, issue - 4, ISSN 2321-7782.

❖◆❖